independent/exclusive coating unit vis-a-vis the integrated mill would depend upon the extent of value addition and the rates of duty applicable.

(c) and (d) Central sales tax and other taxes, if leviable, on purchase of base paper add to the input costs. The effect of such addition would depend upon several factors including the nature and quantity of base paper used, the nature of inputs used, the operations performed on base paper and the rates of taxes.

Representation made to Fifth Pay Commission

976. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Fifth Pay Commission has declined to entertain submission/representation/memoranda etc. made to it by Unions/associations of employees of instrumentalities of Government of India which are fully funded and controlled by the Government of India; and

(b) if so, what is the justification and rationale thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) The Central Pay Commission(s) is/were required to look into emoluments structure etc. of the employees of the Central Government alone. The employees of autonomous/statutory bodies either wholly or substantially controlled and/or financed by the Government are not covered by the terms of reference of the Commission.

काले धन का पता लगाने के लिए योजनाएं

977. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काले धन का पता लगाने के लिए बनायी गयी सभी योजनाएं विफल रही ह ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान काले धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनायें आरंभ की गयीं और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितना-कितना काले धन का पता लगाया गया ?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मर्ति) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए एक योजना आरम्भ की है। राष्ट्रीय आवास बैंक योजना को 1991 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य गन्दी बस्तियों की सफाई और कम लागत वाले आवास बनाने जैसे सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त उपयोग किए जाने हेतु काल धन को जुटाना था। इस योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1992 तक जमा की गई कुल धनराशि 153.8 करोड़ रू० थी।

बकाया विदेशी ऋण

978. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के अन्त में भारत की ओर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया था ;

(ख) किस किस देश से कितना कितना ऋण लिया गया था ;

(ग) इस ऋण पर प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(घ) प्रत्येक देश से ली गयी राशि को कब तक लौटाया है ;

(ङ) क्या पिछली सरकार अथवा वर्तमान सरकार द्वारा इन ऋणों को चुकाने के लिए प्रयास किये गये हैं ; और

(च) यदि हां, तो ऋण की कितनी राशि लौटायी जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992-93 के अंत में कुल विदेशी ऋण (अनिवासी भारतीय जमा राशियां और रक्षा ऋण सहित) की बकाया राशि 90.09 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) नामों और बकाया ऋण की राशि के बारे में विस्तृत जानकारी विदेशी सहायता पुस्तिका-1992:93 और आर्थिक समीक्षा 1993-94 में दी गयी है। इन दोनों दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी हुई हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि 3725 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(घ) और (ङ) इन विदेशी ऋणों का दाताओं के साथ परस्पर सहमत प्रत्येक ऋण करार की शर्तों के अनुसार देय तारीखों को ही भुगतान किया जा रहा है। विदेशी ऋण को जिस गति से कम किया जा सकता है वह चालू खाते में भुगतान संतुलन से संबंधित सम्भाव्य अधिशेष और ऋण भिन्न पूंजी के अंतर्प्रवाह के प्रवाह पर निर्भर करता है। परन्तु इस समय उस वर्ष, जब तक यह सम्पूर्ण विदेशी ऋण चुकता हो जाएगा, के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(च) 1993-94 के दौरान रक्षा और अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़कर 36320 लाख अमरीकी डालर की ऋण की राशियों का भुगतान किए जाने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 के दौरान भुगतान के आंकड़े वर्ष की समाप्ति के बाद संकलित किए जाएंगे।

Introduction of value added tax system

979. MISS SAROJ KHAPARDE: will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether he has recently emphasised the need for further import liberalisation by removing quantitative import restrictions; as per the news report appearing in the Hindustan Times, dated 20th October, 1994 entitled "Value added tax system to be introduced soon"; and

(b) if so, what final decision the Central Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V.CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Yes, Sir. Reduction of quantitative restrictions on imports forms part of Governments declared policy of fostering competitiveness and promoting cost and quality consciousness in Indian Industry.

Assets of UTI

980. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total present assets of UTI;

(b) what had been the total investment mobilization of UTI during the last three years, yearwise;

(c) how many schemes are there in operation wherein UTI has to